कोरोना महामारी के साथ किसानों को आर्थिक संकट से भी बचाने का प्रयास

पूरी दुनिया सहित भारत भी एक तरफ जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है वहीं लॉक डाउन के कारण होने वाले आर्थिक संकट से भी निपटने का प्रयास कर रहा है। केंद्र से लेकर राज्य और पंचायत स्तर तक इसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। आर्थिक स्तर पर एक ओर जहां छोटे उद्योगों को मंदी से बचाने के उपाय किये जा रहे हैं वहीं किसानों को भी उनके फसल को मंडी तक पहुंचाने और उन्हें उसकी वाजिब क़ीमत दिलाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच के सहयोगी संगठन हिमालय पर्यावरण जड़ी बुटी ऐग्रो संस्थान 'जाड़ी' भी अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिल कर इस दिशा में कार्य कर रहा है। इसके तहत समाज में निरंतर जागरूकता अभियान, जरूरतमंदों तक राशन और सरकार के साथ गांव स्तर के मुद्दों की पैरवी का कार्य करने के अतिरिक्त किसानों के हितों के लिए भी प्रयास किये जा रहे है।

इसके लिए संस्था द्वारा एक अभिनव प्रयोग किया गया। जिसमे गांव मे रबी के सीजन में तैयार मटर को बाजार के साथ जोड़ने का था ताकि उपभोक्ताओं को ताजी सब्जी की उपलब्धता हो और साथ ही किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी प्राप्त हो सके। इसके तहत रणनीति बनाई गई और संगठन के सदस्यों ने खेत से लेे कर उपभोक्ता तक पहुंचने की योजना पर तुरंत कार्य शुरू किया। इस प्रक्रिया के तहत जिन तीन प्रमुख पहलुओं पर फोकस किया गया, उनमें सबसे पहले किसान थे। जिनके साथ सदस्यों ने संवाद कर उन्हें

भरोसा दिलाया कि लॉक डाउन की इस मुश्किल घड़ी में उनकी फसलों को बाजार तक पहुंचाने में मदद की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में प्रशासन के साथ तालमेल करके उनकी फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की परमिशन और स्टोरेज की व्यवस्था की गई। तीसरे और अंतिम चरण में जिस विषय पर खास ध्यान दिया गया, वह था बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। ताकि बाजार में भीड़ का दबाव कम हो सके और उपभोक्ता को उसके घर पर ही ताजी सब्जी की उपलब्धता हो सके।

इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य विकास अधिकारी, निम, आईटीबीपी, कलेक्टरेट, कोट बंगला, पुलिस कालोनी हेतू पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, व्यापार मंडल एवम् सब्जी मंडी समिती के साथ संपर्क कर सफलतापूर्वक समन्वय बनाया गया। परिणामस्वरूप एक गांव से शुरू हुए इस प्रयोग में अब तक डूंडा ब्लॉक के 10 गांव के लगभग 55 किसान जुड़ चुके हैं और लगभग 50 कुंतल मटर एवम् 10 कुंतल आलू को बाजार तक पहुँचाया जा चुका है। चूंकि यह आपदा के समय एक मॉडल की टेस्टिंग है इसका उद्देश्य किसी भी रूप मे लाभ कमाना नहीं है। अतः यह भी तय किया गया कि गाड़ी भाड़ा, लेबर, पैकेजिंग मटेरियल आदि के खर्चों को काट कर जो भी धनराशि बचेगी उसे सहकारिता के माध्यम से किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जो इस मुसीबत के समय उनके लिए बहुत मददगार साबित हुई।

जाड़ी और उसकी सभी सहयोगी संस्थाओं का मत है कि कृषि प्रधान इस देश में खेती हमारी आर्थिक रीढ़ है और इस कठिन समय में किसानों के लिए किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप में उनके लिए मददगार साबित होंगे। यही कारण है कि इस प्रयास को तब तक जारी रखी जाएगी जब तक किसानों की समस्त बाजार योग्य फसल की बिक्री ना हो जाए। ताकि उन्हें किसी प्रकार के आर्थिक संकट का सामना नहीं करनी पड़े। उन्हें उम्मीद है कि इस कार्य योजना से किसानों को सभी खर्चे काट कर प्रति किलो 28 से 30 रूपए तक लाभ होगा। इस मॉडल का एक दूसरा पहलू यह भी रहा कि जिस अनियंत्रित योजना के कारण मटर की फसल बाजार में 60 रूपए प्रति किलो बेचीं जा रही थी उसे भी 40 रुपया प्रति किलो तक नियंत्रित करने में कुछ हद तक मदद मिली। जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को भी मिला।

इस योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने से पहले हम सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि क्या ऐसे मॉडल भी आपदाओं में मददगार साबित हो सकते है? लेकिन आज हम कह सकते है कि, हां, विपदा की इस घडी में ऐसे मॉडलों पर काम करने की आवश्यक्ता है। भौगोलिक परिस्थति के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव अवश्य किया जा सकता है। लेकिन योजनाओं को धरातल पर कामयाब बनाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, विश्वास और धैर्य की ज़रूरत है। इस समय देश को कोरोना महामारी के साथ साथ आने वाले आर्थिक संकट से भी निपटने की चुनौती है। ऐसे में यह मॉडल एक छोटी कोशिश ज़रूर है परंतु साहस के साथ उठाया गया कदम वरदान साबित हो सकता है।

द्वारिका प्रसाद सेमवाल
उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच

(उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच सामजिक कार्याकर्ताओ और स्वैछिक संगठनों का एक साझा मंच है, जिसकी स्थापना हिमालय पर्यावरण जड़ी बुटी एग्रो संस्थान जाड़ी की पहल पर 2010 मे आपदा प्रभावितों की पैरवी, सहयोग व सरकार के साथ सामन्जस्य बनाने के उद्देश्य की गई थी।)